

स्वरोजगार मूलक योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्या का विश्लेषण करना

मनीष कुमार सोनी^{1*}, रवि प्रकाश पाण्डेय^{1,2}
¹अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र.)
²शारदा महाविद्यालय मैहर जिला-मैहर (म. प्र.)

सार

सरकारी स्व-रोजगार योजनाओं की चुनौतियाँ भ्रष्टाचार, नौकरशाही की अक्षमता और खराब कार्यक्रम डिज़ाइन के कारण लाभार्थियों तक लाभ पहुँचने से रोकती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन कमियों के कारण लाभार्थियों की उत्पादकता कम होती है और असफलता की दर ज़्यादा होती है। -रोजगार कई व्यक्तियों के लिए एक संतोषजनक और व्यवहार्य करियर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ और विचार भी जुड़े होते हैं। स्व-रोजगार आपको अपने काम पर उच्च स्तर की स्वतंत्रता और नियंत्रण प्रदान करता है। आप अपने प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, अपने काम के घंटे तय कर सकते हैं और बिना किसी बॉस या मैनेजर की अनुमति के निर्णय ले सकते हैं। स्व-रोजगार उन लोगों के लिए एक लाभदायक और लचीला करियर विकल्प हो सकता है जो इससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं।

कीवर्ड: सरकारी रोजगार, कमियाँ और कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ भ्रष्टाचार, नौकरशाही

परिचय

जैसा कि हम दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को देखते हैं, विभिन्न नियमों और व्यवस्था के बिना उचित आचरण और व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस तथाकथित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकारी योजनाएँ और पहल महत्वपूर्ण हैं।

आपको सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। इसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो आप वहन नहीं कर सकते, उसे वहन करने में सरकार आपकी मदद करे। तकनीकी रूप से, इसे सरकार द्वारा राष्ट्र की आबादी के सामान्य कल्याण के लिए तैयार की गई योजना या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन क्षेत्रीय और आय असमानताओं को हमेशा के लिए खत्म करना आसान है।

जैसे सरकार की जिम्मेदारी है कि वह योजनाएँ और सब्सिडी दे, वैसे ही लाभार्थी की जिम्मेदारी है कि वह उनके लिए पात्र हो। इन नीतियों के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो जरूरतमंद हैं और उनके पास मुफ्त सुविधाओं का उपयोग करने का सही उद्देश्य है। जैसा कि हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास आवश्यक कौशल है और वह नौकरी मिलने के बाद अच्छे नतीजे देने के लिए प्रेरित है, लेकिन कुछ कारणों से अभी भी बेरोजगार है, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी कई अन्य योजनाएँ बनाई जाती हैं। इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि व्यक्ति अपने कौशल सेट का सही जगह उपयोग कर सके और उसे बर्बाद न करना पड़े।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ग्रामीण आबादी कुल आबादी का 64.13% है। हम ग्रामीण क्षेत्र में इस भारी बदलाव को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसकी तुलना 1960 में 82% आबादी से करते हैं।¹² ग्रामीण आबादी की जनगणना को साझा करने का मूल कारण यह है कि अधिकांश सरकारी योजनाएँ और सब्सिडी जो डिज़ाइन की जाती हैं, वे एक तरह से सीधे ग्रामीण आबादी के लिए प्रेरित होती हैं। यह शोध पत्र बताता है कि कैसे इन योजनाओं और पहलों को भारत के लोगों द्वारा और उनके लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन और उपयोग किया जाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया में ग्यारहवीं सबसे बड़ी और क्रय शक्ति समता के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी है। स्वतंत्रता के बाद के समाजवादी अर्थव्यवस्था से मजबूत आर्थिक सुधारों के बाद, देश की आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से हुई। तेज आर्थिक विकास के बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक असमानता और उच्च बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, यह भारत में पुरानी बेरोजगारी की विशेषता भी है। पिछले पांच दशकों के दौरान, भारत की जनसंख्या खतरनाक दर से बढ़ी है, जबकि रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। हालाँकि बेरोजगारी को हटाना भारतीय आर्थिक योजनाओं का एक घोषित उद्देश्य रहा है। देश में चार दशकों से अधिक समय से रोजगार सृजन

कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनका विभिन्न पहलुओं और विशिष्ट लक्ष्य समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में रोजगार सृजन के मुद्दे को विभिन्न तरीकों से निपटाया जाता है। जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं कि किसी देश की आर्थिक प्रगति की दर उसके नवाचार की दर पर निर्भर करती है जो बदले में जनसंख्या में उद्यमशीलता की प्रतिभा के वितरण पर निर्भर करती है। तकनीकी प्रगति अकेले आर्थिक विकास की ओर नहीं ले जा सकती जब तक कि तकनीकी सफलताओं का उद्यमियों द्वारा आर्थिक उपयोग न किया जाए। यह उद्यमी ही है जो अपने उद्यम की स्थापना के लिए पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी को सर्वोत्तम संभव तरीके से व्यवस्थित और उपयोग करता है। कुछ समय पहले तक बहुत कम लोग मानते थे कि उद्यमियों को शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से बनाया जा सकता है, या उद्यमिता शिक्षण या प्रशिक्षण का विषय हो सकता है। शुरू में उद्यमिता में शैक्षिक हस्तक्षेप को कम महत्व दिया गया था, लेकिन प्रीफेड मैक्लेलैंड और अन्य जैसे विद्वानों द्वारा सफल प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद, यह साबित हो गया कि उद्यमियों को शिक्षण, प्रशिक्षण और परामर्श हस्तक्षेप के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। तब से प्रगति तेज रही है और अब उद्यमिता लगभग एक आंदोलन बन गई है।

पिछले अध्ययनों का विश्लेषण

सिंह, अमनकुमार. (2023). लेख भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में विस्तार से बताता है। उन योजनाओं ने जो प्रभाव पैदा किया है, वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। लेख में विभिन्न सरकारों द्वारा अब तक लागू की गई सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं की संक्षिप्त समझ शामिल है। लेख में जनगणना के संबंध में डेटा और राष्ट्रीय कल्याण और विकास के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं के डैशबोर्ड विकास को दर्शाया गया है।

कदरोलकर, विलास. (2014). गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम समाज में एक समस्या का समाधान करते हैं, तो दूसरी समस्या भी उसके साथ ही हल हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य में, गरीबी और बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे गंभीर समस्याएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए चयनित लक्षित समूहों के बीच विशेष आय सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। यह नई रणनीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि पिछली योजनाओं और उनकी उपलब्धियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह पाया गया कि आर्थिक विकास का लाभ निम्न आय वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुँच पाया है। अधिकांश ग्रामीण गरीबों के पास बहुत कम या बिल्कुल भी जमीन नहीं है। वे शिक्षित नहीं हैं और उनके पास कोई कौशल नहीं है, इसलिए उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। ग्रामीण युवाओं में कौशल पैदा करने और उन्हें स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए, सरकार ने 'स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM)' नामक एक विशेष योजना लागू की। यह कार्यक्रम अप्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार अपनाने में बहुत सहायक रहा। इसलिए, इस शोध-पत्र में सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना आवश्यक समझा गया है।

धाकर (2024) भारत एक विकासशील देश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सातवाँ सबसे बड़ा देश है। बड़ी जनसंख्या का अर्थ है भारत में एक बड़ा संभावित बाज़ार और देश में रोजगार पर अतिरिक्त दबाव। इस दशक में, भारत स्टार्टअप और व्यापार के अनुकूल माहौल की ओर एक बड़ा बदलाव कर रहा है। प्रतिस्पर्धी माहौल में, भारत अभिनव प्रणाली बनाने के लिए मजबूर है। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के साथ, प्रतिस्पर्धा हर दिन बढ़ रही है, इसलिए लोगों की उद्यमिता के प्रति जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में, उद्यमिता बेरोजगारी और गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं का एकमात्र समाधान हो सकती है: इन लाभों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने देश में उद्यमिता को विकसित करने के लिए समय-समय पर कई पहल की हैं, जैसे कि औद्योगिक नीति और पंचवर्षीय योजना। योजनाएँ मुख्य रूप से लघु क्षेत्र के विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की स्थापना, उद्यमी संस्थानों की स्थापना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EAP) के संगठन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को उद्यमियों की आवश्यकता होती है। भारत की वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बड़े क्षेत्र के सिकुड़ने का दोहन अपेक्षित है, तथा दूसरी ओर वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले अवसर; उद्यमी वास्तव में भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह लेख भारत में उद्यमियों की नई पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का अवलोकन प्रदान करता है। कीवर्ड: स्टार्टअप, नवाचार, नई पीढ़ी। उद्यमी, सरकारी कार्यक्रम।

एलिगनुर, बसवराज। (2023)। यह शोध पत्र भारत में स्टार्टअप पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का एक वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य देश में स्टार्टअप को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों का विश्लेषण और दस्तावेजीकरण करना है। यह शोध पत्र इन योजनाओं से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं, पात्रता मानदंडों, लाभों और चुनौतियों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, यह

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर इन सरकारी पहलों के प्रभाव का आकलन करता है और आगे सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। यह अध्ययन प्रासंगिक साहित्य, आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों और सफल स्टार्टअप के केस स्टडीज की व्यापक समीक्षा पर आधारित है। इस शोध पत्र के निष्कर्ष भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने में सरकार की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

कौसर (2023) भारत में पर्याप्त नौकरियाँ सृजित करने के लिए लगातार सरकारों और नीति निर्माताओं पर दबाव रहा है ताकि भारत के कार्यबल का बेहतर उपयोग किया जा सके और जनसंख्या आर्थिक रूप से मजबूत बनकर आत्मनिर्भर बन सके। नौकरियों का सृजन, कार्यशील जनसंख्या को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने की सुरक्षा के अलावा, गरीबी से लड़ने और व्यक्तियों की बौद्धिक, शारीरिक और कौशल-आधारित क्षमताओं के उचित उपयोग की कमी के लिए भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। जनसंख्या के तेजी से बदलते आयु वितरण के कारण भारत ने अधिकांश विकसित और कम विकसित देशों की तुलना में श्रम बाजार में एक अलग लाभ का आनंद लिया है। भारत ने पहले संकेतक में काफी लगातार बदलाव का अनुभव किया है, खासकर 1991 के सुधारों के बाद, लेकिन रोजगार की प्रवृत्ति ने कोई सुसंगत या स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाया है। हालांकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) हाल के दिनों में श्रमिक से जनसंख्या अनुपात में वृद्धि और रोजगार में लिंग अंतर को कम करता है, भारत का बेरोजगारी परिदृश्य अभी भी निराशाजनक है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले कारकों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती जनसंख्या किस तरह बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। अध्ययन में द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है और भारत में बेरोजगारी के वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शोधपत्र विश्लेषण करता है कि जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी, निरक्षरता, मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार की कमी किस प्रकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मंदा ला सकती है।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तावित अध्ययन पद्धति से तात्पर्य उन व्यवस्थित विधियों से है जिनके द्वारा विद्यार्थी अध्ययन के विषय से संबंधित विश्वसनीय एवं सटीक तथ्यों को एकत्रित कर उन्हें व्यवस्थित करता है।

अध्ययन को वैज्ञानिक और तथ्य आधारित बनाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से डेटा एकत्र किया जाता है, जिसके लिए साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया जाता है। डेटा एकत्र करने के बाद, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है और फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण और चर्चा की जाती है। सीधी जिले में 1997 से 2007 की अवधि में लाभार्थियों की संख्या 8661 है। कुल लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सीधी जिले के चार उपखंडों से लगभग 300 नमूने चुने गए थे। इस प्रकार, नमूना आकार में आनुपातिक का उपयोग करके चयनित 300 लाभार्थी शामिल हैं।

आवश्यकतानुसार, तालिकाओं, ग्राफों और चार्टों का उपयोग किया गया और उन्हें परिष्कृत सांख्यिकीय उपकरणों जैसे सहसंबंध गुणांक (आर), प्रतिगमन गुणांक, ची स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण के साथ पूरक किया गया

डेटा विश्लेषण

भारत जैसे विकासशील देशों में, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की समस्या से निपटने के साधन के रूप में युवा उद्यमिता पर जोर बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं, कौशल विकास पहलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सहयोग से, युवाओं को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजक बनने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य सफल उद्यमियों को आकार देने में कौशल विकास और प्रशिक्षण की भूमिका का पता लगाना और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में स्व-रोजगार से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को समझना है।

• रोजगार जागरूकता योजनाएँ

तालिका 1 स्व-रोजगार योजनाओं के बारे में जागरूकता (n = 300)

जागरूकता स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
पूरी तरह से जागरूक	54	18.0
कुछ हद तक जागरूक	96	32.0

सुना लेकिन स्पष्ट नहीं	81	27.0
जागरूक नहीं है	69	23.0

300 उत्तरदाताओं में से केवल 18% को ही योजनाओं की पूरी जानकारी है, जबकि लगभग 50% को या तो स्पष्टता का अभाव है (27%) या वे अनभिज्ञ हैं (23%)। इससे पता चलता है कि सरकारी जागरूकता कार्यक्रम, खासकर सीधी के दूरदराज के इलाकों में, अपर्याप्त हैं।

तालिका 2 उत्तरदाताओं के बीच योजनाओं की प्राथमिकता (n = 300)

योजना	उत्तरदाताओं का चयन	प्रतिशत (%)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	78	26.0
एनआरएलएम (एसएचजी-आधारित)	102	34.0
पीएमईजीपी	45	15.0
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	39	13.0
आर्थिक कल्याण योजना	36	12.0

समूह-आधारित संरचना और महिलाओं के लिए रिवॉल्विंग फंड समर्थन के कारण एनआरएलएम (34%) सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जबकि आर्थिक कल्याण योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थी कम (12%) हैं। इससे पता चलता है कि ग्रामीण परिवार व्यक्तिगत उद्यमशीलता के जोखिम के बजाय सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

तालिका 3 योजना लाभों के उपयोग का क्षेत्र (n = 300)

क्षेत्र	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
कृषि एवं संबद्ध	93	31.0
उद्योग/विनिर्माण	78	26.0
सेवा (दुकानें, सिलाई, मरम्मत इकाइयाँ)	69	23.0
कौशल-आधारित (प्रशिक्षण केंद्र, आईटी कियोस्क)	36	12.0
अन्य	24	8.0

योजनाएँ कृषि (31%) की ओर ज्यादा झुकी हुई हैं, जो सीधी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। हालाँकि, 26% लघु उद्योगों की ओर और 23% सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं—जो धीमी लेकिन स्पष्ट विविधता को दर्शाता है।

- वित्तीय समस्याएं**

तालिका 4 वित्तीय मुद्दों के प्रकार

वित्तीय मुद्दा	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
अपर्याप्त ऋण राशि	84	28.0

उच्च ब्याज दरें	57	19.0
सब्सिडी/अनुदान न मिलना	72	24.0
पुनर्भुगतान की कठिनाइयाँ	45	15.0
संपार्श्विक/गारंटी संबंधी मुद्दे	42	14.0
कुल	300	100.0

लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने वित्तीय अपर्याप्तता को एक बड़ी बाधा बताया। लगभग 28% ने अपर्याप्त ऋण राशि की शिकायत की, जिसका अर्थ है कि स्वीकृत धनराशि वास्तव में व्यवहार्य व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए बहुत कम थी। इसी प्रकार, 24% ने कहा कि सब्सिडी या सरकारी अनुदान कभी उन तक नहीं पहुँचे, जिससे योजनाओं का अपेक्षित समर्थन कम हो गया। 19% के लिए उच्च ब्याज दरें चिंता का विषय थीं, विशेष रूप से बैंकों और निजी संस्थानों से उधार लेने वालों के लिए, जो पूर्ण भागीदारी को और हतोत्साहित करती हैं। लगभग 15% ने पुनर्भुगतान को कठिन पाया, जबकि 14% को संपार्श्विक या गारंटी आवश्यकताओं से जूझना पड़ा। कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष बताते हैं कि यद्यपि योजनाएँ उपलब्ध हैं, वित्तीय घटक अक्सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है, जहाँ प्रारंभिक निवेश और लचीली पुनर्भुगतान शर्तें महत्वपूर्ण हैं।

- कार्यान्वयन तंत्र में खामियां

तालिका 5 कार्यान्वयन समस्याओं की प्रकृति

समस्या का प्रकार	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
भ्रष्टाचार/रिश्त	57	19.0
मार्गदर्शन का अभाव	96	32.0
अकुशल निगरानी	66	22.0
नौकरशाही देरी	63	21.0
राजनीतिक हस्तक्षेप	18	6.0
कुल	300	100.0

लाभार्थियों ने कई व्यवस्थागत खामियों की पहचान की। सबसे आम शिकायत उचित मार्गदर्शन का अभाव (32%) थी, जो नीतिगत मंशा और जमीनी स्तर पर संवाद के बीच अंतर को दर्शाता है। पर्याप्त प्रशिक्षण या परामर्श के बिना, कई लाभार्थी या तो धन का दुरुपयोग करते हैं या अपनी परियोजनाओं को जारी रखने में विफल रहते हैं। लगभग 22% ने खराब निगरानी की शिकायत की, जो दर्शाता है कि अधिकारी अक्सर प्रारंभिक धनराशि जारी होने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं करते हैं। नौकरशाही देरी (21%) और रिश्त के रूप में भ्रष्टाचार (19%) को भी प्रमुख बाधाओं के रूप में उजागर किया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप, हालांकि कम बार (6%) होता है, फिर भी योजनाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है जब वास्तविक आवेदकों को राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियाँ योजनाओं की प्रभावशीलता को काफी कम कर देती हैं।

- उद्देश्यों और लक्ष्य से संबंधित खामियां

तालिका 6 योजना के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता

जागरूकता स्तर	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
पूरी तरह से जागरूक	72	24.0
आंशिक रूप से जागरूक	111	37.0
जागरूक नहीं है	117	39.0
कुल	300	100.0

योजना के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता चिंताजनक रूप से कम है। केवल 24% उत्तरदाताओं को पूरी जानकारी थी, जबकि 37% को आंशिक रूप से जानकारी थी। 39% लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, यह दर्शाता है कि सरकारी प्रचार और अभिविन्यास अभियान अपर्याप्त हैं। योजना के उद्देश्यों की उचित जानकारी के बिना, लाभार्थी अपने प्रयासों को अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं बना पाते, जिससे लाभों का कम उपयोग होता है। यह एक महत्वपूर्ण संचार अंतराल को उजागर करता है जो प्रभाव को सीमित करता है।

- कार्यान्वयन में देरी

तालिका 7 अनुभव की गई देरी के प्रकार

विलंब प्रकार	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
ऋण स्वीकृति में देरी	99	33.0
निधि संवितरण में देरी	81	27.0
प्रशिक्षण में देरी	60	20.0
दस्तावेज़ीकरण में देरी	45	15.0
अन्य	15	5.0
कुल	300	100.0

देरी व्यापक और बहुआयामी थी। सबसे बड़ी बाधा ऋण स्वीकृति (33%) थी, जो अक्सर अत्यधिक कागजी कार्रवाई और लंबी स्वीकृति श्रृंखलाओं के कारण होती थी। धन वितरण में देरी भी आम थी (27%), जिससे लाभार्थियों के लिए समय पर अपना व्यवसाय शुरू करना मुश्किल हो गया। प्रशिक्षण में देरी से 20% लोग प्रभावित हुए, जिससे लाभार्थी व्यवसायों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार नहीं हो पाए। दस्तावेज़ीकरण में देरी (15%) और अन्य छोटी-छोटी समस्याओं ने निराशा को और बढ़ा दिया। कुल मिलाकर, देरी लाभार्थियों का मनोबल गिराती है और कभी-कभी उन्हें योजनाओं को पूरी तरह से छोड़ने पर मजबूर कर देती है।

- वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है

तालिका 8 बहिष्करण के कारण

बहिष्करण कारण	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
नौकरशाही पूर्वाग्रह	69	23.0
जागरूकता की कमी	87	29.0
आवश्यकता के बावजूद अयोग्यता	72	24.0
कोटा समाप्त	45	15.0
अन्य	27	9.0
कुल	300	100.0

आँकड़े बताते हैं कि जागरूकता की कमी (29%) वास्तविक लाभार्थियों के लाभ प्राप्त न कर पाने का सबसे बड़ा कारण है। ज़रूरतमंद होने के बावजूद, 24% को कठोर दिशानिर्देशों के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया। 23% ने नौकरशाही पूर्वाग्रह का हवाला दिया, जहाँ पक्षपात या राजनीतिक प्रभाव ने निष्पक्ष चयन में बाधा डाली। सीमित कोटा (15%) ने भी कई लोगों को लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया। ये बहिष्करण कारक योजनाओं की समग्रता को कमजोर करते हैं, और अक्सर सबसे गरीब लोगों को पीछे छोड़ देते हैं।

निष्कर्ष

स्व-रोज़गार कई व्यक्तियों के लिए एक संतोषजनक और व्यवहार्य करियर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ और विचार भी जुड़े होते हैं। स्व-रोज़गार आपको अपने काम पर उच्च स्तर की स्वतंत्रता और नियंत्रण प्रदान करता है। आप अपने प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, अपने काम के घंटे तय कर सकते हैं और बिना किसी बॉस या मैनेजर की अनुमति के निर्णय ले सकते हैं। स्व-रोज़गार उन लोगों के लिए एक लाभदायक और लचीला करियर विकल्प हो सकता है जो इससे जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यह स्वतंत्रता, संभावित वित्तीय लाभ और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

संदर्भ

- साहा, अमित (2018). उद्यमिता सशक्तिकरण: भारत में महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं पर एक अध्ययन।
- अहमद, जमील. (2021). स्वरोजगार को बढ़ावा देने में कौशल भारत की भूमिका: संभावनाएँ और चुनौतियाँ. विशेषांक. 185-190.
- स्वरूपा, ग्लोरी और गोयल, रवि (2019)। स्वरोजगार के लिए कौशल विकास।
- नाइक, अमी और पटेल, पूजा। (2022)। उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए सरकारी योजनाएँ। 10.1007/978-981-19-5747-5_21
- गुप्ता, पवन कुमार. (2023). भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों का एक अध्ययन. मैनेजमेंट जर्नल फॉर एडवांस्ड रिसर्च. 3. 10.54741/mjar.3.6.5.
- डॉ. अब्दाल और कुरैशी, सुमेरा और नरगिस, शमा और कौर, जसमीत और डबराल, डॉ. (2024)। महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने वाली भारतीय सरकार की योजनाओं का व्यापक विश्लेषण। 19. 2024. 10.18848/6z5mxs52.

7. सिंह, रागिनी. (2024). भारत में एमएसएमई के विकास में सरकारी सहायता योजनाओं की भूमिका पर एक अध्ययन. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. 4. 127-132. 10.3126/jem. v4i1.72897.
8. मुस्तफा, श्रीमती और खान, शुजाउद्दीन. (2024). गरीबी उन्मूलन में भारत सरकार की योजनाएँ. 06. 2913-2931. 10.6084/m9.figshare.2631195.
9. कौसर, अनिसुर और बोरमोन, सयानिका। (2023)। बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के बीच भारत में स्वरोजगार: चल रहे अंतर्निहित निर्धारकों पर प्रकाश डालना। शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 4. 10.29121/shodhkosh. v4.i2.2023.2105।
10. एलिगनूर, बसवराज. (2023). भारत में स्टार्टअप पहल के लिए सरकारी योजनाओं पर एक वर्णनात्मक अध्ययन. 47. 113-120.
11. धाकर, शुभी और सिरिया, सुश्री (2024)। भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर एक अध्ययन। 18. 76-82।
12. कद्रोलकर, विलास. (2014). ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार सृजन: कौशल सृजन कार्यक्रम का एक अध्ययन. प्रशिक्षण और विकास जर्नल. 4. 29-36. 10.5958/j.2231-069X.4.1.
13. सिंह, अमनकुमार. (2023). भारत सरकार की योजनाओं और पहलों पर एक अध्ययन: एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य. 10.13140/RG.2.2.19282.94407.
14. अमृता सोमशेखर¹ और सैयद सैफ² (2022), “एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाओं और भारत के विकास में उनके योगदान का एक अध्ययन,” सेंट जोसेफ जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च ई-आईएसएसएनवॉल-1(01)
15. अंगूरी, सुखविंदर और धनखड़, सौरभ और कुमार, संजीव। (2022)। पीएम स्वनिधि और कोविड-19 संकट के बाद स्वरोजगार वाले अनौपचारिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में इसकी भूमिका। सामाजिक अर्थव्यवस्था और नीति अध्ययन। 2. 61-66। 10.26480/सेप्स.02.2022.61.66।